प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 18-25 सितम्बर 2017 मूल्य पांच रूपए

क्या सरकार तिलकराज प्रकरण में सीबीआई को अभियोजन की अनुमति देगी

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलक राज के रिश्वत प्रकरण में सीबीआई ने चण्डीगढ़ ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर दिया है। बल्कि यह चालान दायर होने के बाद ही तिलक राज को जमानत मिली और वह फिर से नौकरी पर आ गये हैं। लेकिन सीबीआई के इस चालान को आगे बढ़ाने के लिये इसमें सरकार की ओर से अभियोजन की अनुमति चाहिये जो कि अभी तक सरकार ने नहीं दी है। सेवा नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अपराधिक मामला चलाने के लिये अभियोजन की अनुमति अपेक्षित रहती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में यह व्यवस्था दे चुका है कि जब सरकारी कर्मचारी उस पद से हट चुका हो जिस पद पर रहते उसके खिलाफ ऐसा मामला बना था तब ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नही रह जाती है। तिलक राज के खिलाफ जब यह मामला बना था तब वह बद्दी में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे लेकिन यह कांड घटने पर सीबीआई ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया और जमानत मिलने के बाद विभाग ने उन्हे बद्दी से बदलकर शिमला मुख्यालय में तैनात कर दिया है। शिमला में उन्हे जो काम दिया गया है उसका उनके बद्दी में रहते किये गये काम से कोई संबंध नही है। काम की इस भिन्नता के चलते विभाग के अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग अभियोजन की अनुमति दे दिये जाने के पक्ष में था लेकिन कुछ लोग अनुमति के नाम पर इस मामले को लम्बा लटकाने के पक्ष में हैं और इस नीयत से इस मामले को विधि विभाग की राय के लिये भेज दिया गया है। जबकि नियमों के अनुसार इसमें अन्तिम फैसला तो उद्योग मन्त्री के स्तर पर ही होता है।

उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग को मामला भेजने के लिये जो आधार बनाया गया है कि जब तिलक राज पर छापा मारा गया था उस समय सीबीआई ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नही कर रखी थी। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि पैसे की रिकवरी भी तिलक राज से न होकर अशोक राणा से हुई है जो कि सरकारी कर्मचारी नही है। लेकिन इस मामले में जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर रखी है उसके मुताबिक 29 मई को यह मामला विधिवत रूप से दर्ज हो गया था और तिलक राज से रिकवरी 30 मई को हुई थी। रिकवरी के बाद ही अगली कारवाई शुरू हुई थी। ऐसे में विभाग का यह तर्क है कि छापेमारी से पहले एफआईआर दर्ज नही थी कोई ज्यादा पुख्ता नही लगता। एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक इसमें बद्दी के ही एक फार्मा उद्योग के सीए चन्द्र शेखर इसके शिकायत कर्ता हैं। शिकायत के मुताबिक चन्द्र शेखर ने फार्मा उद्योग की 50 लाख सब्सिडी के लिये 28 मार्च को बद्दी में संयुक्त निदेशक तिलक राज के कार्यालय में दस्तावेज सौंपे थे। दस्तावेज सौंपने के बाद चन्द्र शेखर को एक अशोक राणा से संपर्क करने के लिये कहा जाता है, इसके बाद 22 मई को उसे इस संद्धर्भ में विभाग का नोटिस मिलता है और फिर वह अशोक राणा से मिलता है तथा इस दौरान हुई बातचीत रिकार्ड कर लेता है। चन्द्रशेखर की बातचीत अशोक राणा से 19 मई और 22 मई को होती है। इसमें उससे रिश्वत मांगी जाती है। चन्द्रशेखर यह रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सीबीआई से 27 मई को करता है और प्रमाण के तौर पर यह रिकार्डिंग पेश करता है। सीबीआई अपने तौर पर 28 और 29 मई को स्वयं इस बातचीत और रिकार्डिंग की व्यवस्था करती है। जब 29 मई को इस तरह सीबीआई की वैरीफिकेशन पूरी हो जाती है तब उसी दिन 29 को यह एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद 30 को यह रिश्वत कांड घट जाता है, और सीबीआई तिलक राज को गिरफ्तार कर लेती है।

एफआईआर में दर्ज इस विवरण से विभाग द्वारा अब अभियोजन की अनुमति के लिये लिया गया स्टैण्ड मेल नही खाता है। तिलक राज की गिरफ्तारी के बाद उसके कांग्रेस सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार में शीर्ष तक उसके घनिष्ठ संबंधों की चर्चा जगजाहिर हो चुकी है। क्योंकि एफआईआर के मुताबिक ही यह रिश्वत का पैसा मुख्यमन्त्री के दिल्ली स्थित ओएसडी रघुवंशी को जाना था। अब रघुवंशी भी इस मामले में सीबीआई के एक गवाह हैं। ऐसे में अब यह मामला एक ऐसे मोड़ पर है जहां सबकी नजरें इस ओर लगी है कि क्या उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री इसमें अभियोजन की अनुमति देते है या नही? क्या सीबीआई इसमें अनुमति के बिना ही इस मामले को अंजाम तक पंहुचा पायेगी या नही।

क्यों मेहरबान है सरकार डा.बवेजा पर?

शिमला/शैल। कुछ समय पहले तक निदेशक बागवानी और एमडी कृषि विपणन बोर्ड का एक साथ कार्यभार संभाल रहे डा. एचएस बवेजा को अब सरकार ने स्थायी रूप से कृषि बोर्ड कार्यभार सौंप दिया है। डा. बवेजा जब निदेशक बागवानी थे उस समय ठियोग के पास बन रहे एक कोल्ड स्टोर की सब्सिडी के मामले में काफी विवाद उठा था। कोल्ड स्टोर बना रही कंपनी ने डा. बवेजा के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत भी सरकार को भेजी थी। शिकायत में आरोप था कि सब्सिडी रिलिज करने के लिये दो करोड़ रूपये की मांग की गयी थी लेकिन सरकार ने इस शिकायत पर कोई कारवाई न करके अब इस तरह से उन्हे राहत प्रदान कर दी है। जबकि ऐसी शिकायतों को तुरन्त विजिलैन्स को भेजकर जांच करवाई जाती है लेकिन बवेजा के मामले में ऐसा नही हुआ।

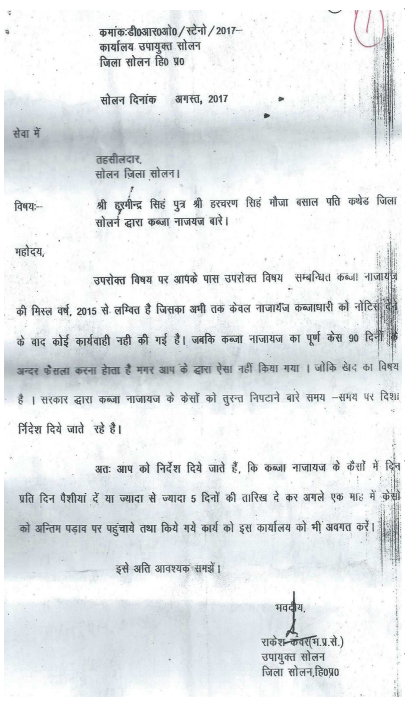

क्रमांकःडी0आर0ओ0/स्टेनो/2017-
कार्यालय उपायुक्त सोलन
जिला सोलन हि0 प्र0

सोलन दिनांक अगस्त, 2017

सेवा में

तहसीलदार,
सोलन ज़िला सोलन।

विषयः- श्री हुर्मीन्द्र सिहं पुत्र श्री हरचरण सिहं मौजा बसाल पति कथेड जिला सोलन द्वारा कब्जा नाजयज बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पास उपरोक्त विषय सम्बन्धित कब्जा नाजायज की मिस्ल वर्ष, 2015 से लम्वित है जिसका अभी तक केवल नाजायज कब्जाधारी को नोटिस देने के वाद कोई कार्यवाही नही की गई है। जबकि कब्जा नाजायज का पूर्ण केस 90 दिनों के अन्दर फैसला करना होता है मगर आप के द्वारा ऐसा नहीं किया गया । जोकि खेद का विषय है । सरकार द्वारा कब्जा नाजायज के केसों को तुरन्त निपटाने बारे समय -समय पर दिशा निर्देश दिये जाते रहे है।

अतः आप को निर्देश दिये जाते हैं, कि कब्जा नाजायज के कैसों में दिन प्रति दिन पैशीयां दें या ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों की तारिख दे कर अगले एक माह में केसों को अन्तिम पड़ाव पर पहुंचाये तथा किये गये कार्य को इस कार्यालय को भी अवगत करें।

इसे अति आवश्यक समझें।

भवदीय,
राकेश कंवर(भ.प्र.से.)
उपायुक्त सोलन
जिला सोलन,हि0प्र0

यही नही डा. बवेजा के खिलाफ सोलन के चंबाघाट में 374 वर्गमीटर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने का मामला भी अभी तक लंबित चल रहा है। इस अक्रिमण की जांच करके ग्रामीण राजस्व अधिकारी वृत बसाल त. सोलन ने 8.10.2015 को रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 163 के तहत कारवाई किये जाने का मामला पाया गया था। नियमानुसार इस रिपोर्ट के बाद डा. बवेजा के खिलाफ कन्डक्ट रूल्ज 1964 के तहत कार्यवाही हो जानी चाहिये थी। क्योंकि 14 सितम्बर 2005 को इस संद्धर्भ में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नियम 4.A के उल्लेख में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इन अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिये हुए हैं। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों पर कारवाई करते हुए कई बागवानों को बागीचों से हाथ धोना पड़ा है। इन्ही निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिलाधीश सोलन ने अगस्त 2017 में तहसीलदार सोलन को इनमें तुरन्त प्रभाव से कारवाई करने के निर्देश जारी किये हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक आगे कोई बड़ी कारवाई नही हुई है।

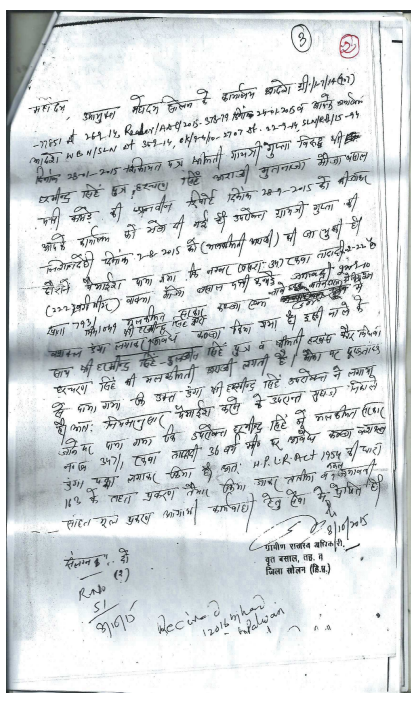

"4-A. No Government servant shall encroach upon Government land himself or through/by his family members."

By Order
S.S.Parmar
Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh

contd.. 2 .

सरकार का डा. बवेजा के प्रति ऐसा नरम रूख क्यों है कि उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई कारवाई होती ही नही है। इस संद्धर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 2012 में जब डा. बवेजा नौणी विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे तब एक मामले में इनके खिलाफ जांच के आदेश हुए थे और इसके लिये 21.7.12 को सेवानिवृत सैशन जज ओपी शर्मा को जांच अधिकारी लगाया गया था। लेकिन डा. बवेजा ने ओपी शर्मा

को जांच अधिकारी लगाये जाने का विरोध किया। इस विरोध के बाद ओपी शर्मा के स्थान पर 14.8.2012 को ही सेवानिवृत आईएएस अधिकारी राकेश कौशल को जांच सौंप दी गयी। लेकिन बवेजा ने कौशल को जांच अधिकारी लगाये जाने का भी विरोध किया। जब सरकार ने उनके विरोध को स्वीकार

शेष पृष्ठ 8 पर..............

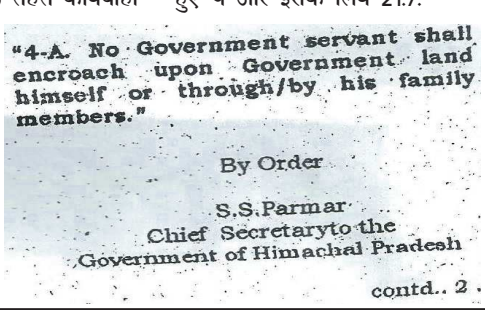

www.shailsamachar.co.in

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें
कार्यालय दूरभाष - 0177 - 2805015, मो. 8988587014, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in
पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

वैज्ञानिकों का समर्पण व प्रयास हिमाचल को बनाएंगे जैविक राज्य– राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश को देश का शून्य बजट प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य इन उत्पादों के लिए अपनी मण्डी विकसित करेगा ताकि किसानों को इन मण्डियों में उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।

राज्यपाल राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय सोसायटी के हिमाचल चैप्टर द्वारा डॉक्टर वाई. एस परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के सहयोग से विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक कृषि प्रणाली पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण के लिए स्वस्थ एवं उपयोगी है। उन्होंने कहा कि यह अति आवश्यक है कि रसायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में बदला जाए ताकि भूमि की उर्वरकता में आ रही कमी व कृषि फसलों में रसायनिक खादों की भारी मात्रा के उपयोग से स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने में वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हांने कृषि वैज्ञानिकों से समर्पण की भावना से कार्य करने का आग्रह किया तथा कहा कि कृषि देश के लोगों की आर्थिकी की रीढ़ है।

राज्यपाल ने कहा कि यदि वैज्ञानिक प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में कार्य करने के लिए समर्पित हों तो कोई भी प्रदेश को सिक्किम की तरह जैविक राज्य बनने से नहीं रोक सकता। इससे रसायनिक खाद और कीटनाशक बेचने वाली कम्पनियों के एकाधिकारी पर भी रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती राष्ट्र को कृषि क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद न केवल स्वस्थ जीवन में सहायता करते है अपितु पर्यावरण समृद्धि में भी सहायक है।

राज्यपाल ने कहा कि पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने देश के किसानों का मार्गदर्शन कर उन्हें शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा दी जिसे देश के 40 लाख से अधिक किसानों ने अपनाया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक लोगों को लम्बे समय तक लाभान्वित करेंगी और इस तकनीक को अपनाने वाले किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक स्थानीय गाय 30 एकड़ भूमि पर कृषि के लिए सहायक होगी और इससे भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी और कम पानी के उपयोग से अधिकतम उपज प्राप्त होगी और किसान अपने उत्पादों का लाभदायक मूल्य प्राप्त कर सकेगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने निजी हितों से उपर उठकर कार्य करना चाहिए और प्राकृतिक खेती पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे देश के किसानों की आय को दुगुना करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने डॉक्टर करतार सिंह को कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में योगदान देने के लिए लाईफ टाईम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया।

पदम श्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने कृषि वैज्ञानिकों को कार्यशाला आयोजित करने को बधाई दी तथा कहा कि यह आज नितान्त आवश्यक है कि वैज्ञानिक किसानों को वैकल्पिक खेती उपलब्ध करवाएं, जिससे उनकी आय दुगुनी हो सके। उन्होंने कहा कि समाज के समक्ष खाद्य सुरक्षा, वैश्विक उष्मीकरण गांव से प्लायन तथा एकल परिवार के बढ़ने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपनाएं जा रहे कृषि के ढंग वैश्विक उष्मीकरण के लिए जिम्मेवार है और सभी चुनौतियों को शून्य बजट प्राकृतिक खेती से सुलझाया जा सकता है और वैज्ञानिकों को इससे निपटने के लिए समाधान देने चाहिए।

महिला सशिक्तकरण केवल शिक्षा द्वारा संभव:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों में मानवीय मूल्यों स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण जैसे सर्वोपरि लक्ष्य की जिम्मेवारी शिक्षकों के कंधों पर है।

राज्यपाल शिमला के एतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाजार के वार्षिक समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय से राष्ट्र निर्माण की चुनौती को समर्पित भाव से अपनाने का आग्रह किया क्योंकि शिक्षक बच्चों के साथ-साथ देश के भविष्य को तय करने में भी अह्म भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का छात्रों पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है जिससे उन्हें उच्च मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने व बाल अवस्था में उनके चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि छात्रों को राष्ट्र के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर शिक्षा के सही मायनों को हासिल करना चाहिए।

उन्होंने युवाओं से सभी प्रकार की सामाजिक बुराईयों से मुक्त स्वच्छ व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें अपने समृद्ध पारम्परिक साहित्य के पारम्परिक मूल्यों व प्राचीन ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है, जिसे वर्तमान युग में लगभग भुलाया जा चुका है। उन्होंने महिलाओं को समाज में उचित दर्जा व सम्मान प्रदान कर महिला सशिक्तकरण व कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया।

आचार्य देवव्रत ने स्वामी दयानन्द के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वामी ने न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति की शान को पुनर्बहाल किया, बल्कि समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों को दूर करने की भी नींव रखी। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा व महिलाओं का उत्थान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पर था। उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को सशक्त करना अति आवश्यक है और उन्हें शिक्षित कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विधवा पुर्न: विवाह को बढ़ावा देने तथा समाज में व्याप्त बुराईयों के विरूद्ध आवाज उठाने का भी आहवान किया।

राज्यपाल ने डीएवी संस्थान की गुणात्मक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए सराहना की।

उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके प्रयासों की भी सराहना की।

डीएवी प्रबन्धन समिति की अध्यक्ष व आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली की अध्यक्ष पदमश्री डा. पूनम सूरी ने देश के 23 राज्यों में डीएवी संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही गुणात्मक शिक्षा बारे जानकारी दी। उन्होंने अध्यापकों के प्रयासों की भी सराहना की जिनके प्रयासों की बदौलत डीएवी ने सफलता की उंचाईयां हासिल की हैं।

डीएवी पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाजार की प्रधानाचार्य कामना बेरी ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि स्कूल ने शैक्षणिक, खेल व अन्य गतिविधियों में अभूतपूर्वक प्रगति की है और आज यह शिमला का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान बन कर उभरा है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

लेडी गर्वनर दर्शना देवी, डीएवी केन्द्रीय प्रबन्धन समिति नई दिल्ली के सदस्य, स्थानीय समिति के निदेशक, कर्मचारी, विद्यार्थी व अभिभावक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER SHIMLA DIVISION NO. III, HPPWD SHIMLA-3.
WEB: WWW.HPPWD.GOV.IN EMAIL: EE-SML3-HP@NIC.IN PHONE/ FAX NO.:- 0177-2652832.
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Shimla Division No. III, HP.PWD. Shimla-3 on behalf of the Governor of H.P. for the following works from the eligible Contractors/Firms enlisted in HP.PWD, so as to reach in his office on or before 26-10-2017 up to 10.30 A.M. and will be opened on the same day at 11.00 A.M. in the presence of the intending Contractors/Firms or their authorized representatives. The tender form can be had from his office against cash payment (non-refundable) on any working day up to 4.00 P.M. on 25-10-2017 and the application for issue of tender form shall be received up to 4.00 P.M. on 24-10-2017. The earnest money in the shape of National saving Certificate/Time deposit account/saving account in any of the post office in HP, duly pledged in favour of Executive Engineer, Shimla Division No-III must accompany with the application form for the tender offer. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason there to. Other conditions are applicable as perform No. 6&8. The offer shall remain open for 90 days.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Form No	Cost of form
1.	S/R to High ourt Building at Shimla. (SH:- P/F HDF decorative laminate core board Krono (Original) flooring in Judges Chamber 3rd floor to 6th floor and Registrar General office on 7th floor).	Rs.5,01,166/-	Rs.10,030/-	One Month	6&8	350/-
2.	S/R to High ourt Building at Shimla. (SH:- P/F tileswork,Cupboard, Paneled Glazed shutter, Steelwork, CGI Sheet roofing, painting, distempering and sanitary work etc.in Old Judges Lounge for Establishment of Gymnasium).	Rs.2,20,191/-	Rs.4,410/-	One Month	6&8	350/-
3.	S/R to Medical College at IGMC Shimla (SH: P/F railing in Hollow Section and tiles work in floor and steps etc.).	Rs. 2,15,352/-	Rs. 4,310/-	One Month	6&8	350/-
4.	S/R to various residential building at Holly Oak at Sanjauli Shimla.(SH:- P/F Cupboard, wood work tiles work painting and distempering etc. in block-A, type-II &III, set No. 1 to 5).	Rs. 2,06,083/-	Rs. 4,130/-	One Month	6&8	350/-
5.	S/R to Ambulance road fromm Lakkar Bazar to Correstophen Estate Shimla.(SH:- C/O Edge wall at RD's 0/00 to 0/060, 0/065 to 0/105).	Rs. 2,00,444/-	Rs.4,010/-	One Month	6&8	350/-
6.	A/R & M/O residential building at Correstophen Estate at IGMC Shimla. (SH:-Repair of gate, railing and fencing etc.).	Rs. 1,39,465/-	Rs.2,790/-	One Month	6&8	350/-
7.	S/R to High Court building at Shimla. (SH:- C/O new stand for water purifier, painting in toilets of main building and Old building repair work etc.).	Rs. 1,74,862/-	Rs.3,500/-	One Month	6&8	350/-

Terms & Conditions:-
1. The contractor/firm shall have his Sale Tax No. and attested copy of the same be attached with the application for issue of tender form.
2 . The contractor/firm should attach attested copy of registration/renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form

Adv. No.-2811/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER

Sealed item rate tenders on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer Fatehpur Division HPPWD., Fatehpur on behalf of the Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1.	Date and time of receipt of application for tender form:	30.10.2017upto 2 .00 PM
2.	Date and time of issue of tender form:	31.10.2017upto 5.00 PM
3	Date and time of receipt of tenders:	01.11.2017upto 10.30AM
4	Date and time of opening of tenders:	01.11.2017 at 11.00 AM

The tenders form will be issued against cash payment (non refundable). The earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any of Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the Executive Engineer, Fatehpur Division HPPWD Fatehpurmust accompany with each tender.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of form	Eligible class of Contractor
1.	Construction of road from link road to Village Blerch in G.P.Dhameta Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (HP) (SH:- Construction of 3.00 mtrs. Span RCC slab culvert at RD. 0/730 and construction of cement concrete pavement in km. 0/0 to 0/120)	459186/-	9200/-	One month	350/-	D& C
2.	Improvement of Black spot on Pong Dam Fatehpur Jassur road km. 0/0 to 25/0 (SH:-Construction of retaining wall at RD. 19/830 to 19/842)	1,10,120/-	2200/-	One month	350/-	-do-
3.	A/R & M/O Assistant Engineer,HPPWD,. Sub-Division, Dhameta (SH:- Construction of boundary wall in the surrounding camps of Assistant Engineer,HPPWD, Sub-Division Dhameta= 80.00 Mtrs.)	1,39,498/-	2800/-	One month	350/-	-do-
4.	Construction of BharwainChintpuraniKhatiar Rey Damtal road (SH:- Construction of solid causeway at RD. 5/720)	1,27,740/-	2600/-	One month	350/-	-do-
5.	Restoration of rain damages due to laying OFC on Pong Dam FatehpurJassur road km 25/0 to 33/0 (SAH:- Construction of Breast wall at RD. 30/325 to 30/550 and construction of U-shape drain at RD. 30/280 to 30/415 Length 135mtrs.	2,54,269/-	5100/-	One month	350/-	-do-
6.	A/R & M/O SunharaTakwalReing road km. 0/0 to 2/720(SH:- Construction of retaining wall at RD. 0/520 to 0535 and 1/0 to 1/010) under road safety Removal of Black Spot)	3,92,074/-	7900/-	One month	350/-	-do-
7.	A/R & M/O link road from MairaPalli road to Village TakoliGhirthan km. 0/0 to 1/500 (SH:- Providing and laying cement concrete pavement at RD. 0/360 to 0/425, 0/610 to 0/635 and 0/635 to 0/665)	1,68,451/-	3400/-	One month	350/-	-do-
8.	A/R & M/O Madholi to Ram nagar km. 4/0 to 5/0(SH:- Construction of cement concertepoavement from RD. 4/300 to 4/400)	1,56,671/-	3200/-	One month	350/-	-do-

1.The contractors/firms should possess the following documents(Photocopy to be attached):
(i) Latest renewal of enlistment.
(ii) PAN (Permanent Account No.)
(iii) Registration under HP General Sale Tax Act, 1968 (TIN No.).
2. Ambiguous/telegraphic/conditional tenders or tender by Fax/E-mail shall not be entertained / considered in any case.
3. The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).
4. Only two tendersshall be issued to each contractor

Adv. No.-2843/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

जन प्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी सरकार के कार्यक्रमों के प्रति लोगों को करें जागरूक:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। पंचायत जन प्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी लोगों के बीच पहुंचकर सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही नीतियों व कार्यक्रमों के बारे जागरूक करें ताकि वर्तमान प्रदेश सरकार के शासनकाल के दौरान लोगों के कल्याण के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों व योजनाओं से लोग लाभान्वित हो सके।

मुख्यमंत्री सोलन जिला के कुमारहट्टी में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने 6 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत चेवा के कुमारहट्टी में बहुउद्देशीय हॉल तथा खेल मैदान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के नाम पर बनाए गए इस परिसर का निर्माण विकास में जन सहयोग योजना के अन्तर्गत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के लोगों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना होता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर गर्व होता है कि हिमाचल प्रदेश बड़े राज्य की श्रेणी में उच्च शिक्षा क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य आंका गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं विशेषकर लड़कियों को उनके घरद्वार के निकट गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है तथा सरकार ने 'बेटी है अनमोल' योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की लड़कियों को स्नातक स्तर व इसके समकक्ष पाठयक्रमों जिनमें इंजीनियरिगं स्नातक, बीटैक, एमबीबीएस, बीएड व एलएलबी कोर्स शामिल है को 5 हजार रूपये की वार्षिक छात्रवृति देने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता प्रदान कर रही है। बेरोजगार युवाओं की दक्षता तथा रोजगार उन्मुख अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रूपये की कौशल विकास योजना आरम्भ की गई है।

वीरभद्र सिंह ने 4 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले कुष्ठ रोग अस्पताल लोहांजी के नए भवन की आधारशिला रखी। यह भवन प्री-फैबरीकेटिड ढांचे के रूप में बनाया जाएगा।

उन्होंने धर्मपुर में 3.86 करोड़ रू. की लागत से निर्मित होने वाले खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन तथा 34 लाख रूपये की लागत से सुल्तानपुर मड़ीघाट डिलमन पर कांगर पुल की भी आधारशिला रखी ।

मुख्यमंत्री ने 1.47 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित क्यिरूवा-जनदोरी उठाऊ पेयजल योजना तथा गांधीग्राम में 5 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित 33 केवी विद्युत उप केन्द्र का भी लोकार्पण किया। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला दभोग को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

मुख्य सचिव ने लिया विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभिन्न विभागों जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सूचना एवं जन सम्पर्क, परिवहन, पुलिस, आबकारी एवं काराधान, आयकर, राष्ट्रीय सूचना, सूचना एवं तकनीकी, दूरभाष विभाग, डाक सेवाएं एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल है की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे पॉवर प्वांइट की प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया गया।

फारका ने प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों को आवश्यक अधोसंरचना के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा तथा कल्याण विभाग को दिव्यांगों के लिए रैम्प तथा व्हील चेयरों की सुविधाएं प्रदान करने को कहा ताकि वे सुगमता से अपना मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि दो स्वयं सेवी मतदाताओं की सुविधाओं के लिए तैनात किए जाएंगे।

उन्होंने बैठक में विधानसभा चुनाव-2017 के लिए डाक द्वारा मतदान की सुविधा के बारे बताया कि इसे इस बार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। फारका ने सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य के कोने-कोने तक मतदाताओं को शिक्षित तथा उनकी मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए अभियान चलाने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने कठिन एवं अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति तैनात करने के निर्देश दिए ताकि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक संख्या में पुलिस जवानों जिनमें होम गार्ड व पैरा-मिल्ट्री जवान भी शामिल है का समय पर प्रबन्ध करने को कहा। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को सभी मतदान केन्द्रों पर पेजयल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने तथा विद्युत बोर्ड को मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को भी कहा। उन्होंने दूरभाष विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बाधा रहित दूरभाष सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने प्रदेश के संवेदनशील तथा अति-संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और इसके लिए आवश्यक पुलिस बल तैनात करने को भी कहा।मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र राजपूत ने कार्यवाही का संचालन किया।

नौतोड़ मामलों को तत्काल निपटाने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 'नौतोड़' के मामलों को बिना किसी विलम्ब के निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण अधिकारियों को मौके पर जाकर दी गई समय सीमा के भीतर 'नौतोड़' की स्वीकृतियां निपटानी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद् की 46वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौतोड़ में रियायत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत एक सीमित अवधि के लिए प्रदान की गई थी तथा सभी उपायुक्तों को बिना किसी विलम्ब से नौतोड़ प्रदान करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को उपदान पर ईमारती लकड़ी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें ईमारती लकड़ी की वास्तविक मूल्य पर 76.26 प्रतिशत के अनुदान के अतिरिक्त 80 प्रतिशत परिवहन उपदान भी शामिल है।

बैठक में लंगछा पंचायत के कॉमिक गौम्पा में ईमारती लकड़ी का डिपो खोलने का निर्णय भी लिया गया।

मुख्यमंत्री ने रूकटी पॉवर हाउस की अक्रीयशीलता का संज्ञान लेते हुए कहा कि इस परियोजना के जीर्णोद्धार तथा मशीनरी व उपकरणों पर काफी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा उन्होंने निर्देश दिए कि इसे बिना किसी देरी से कार्यशील बनाया जाए।

बैठक में किन्नौर के लोगों को द्वि-मासिक विद्युत बिल प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है तथा जिला किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गो को पक्का करने के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जिला लाहौल स्पिति के उदयपुर मण्डल के अन्तर्गत चनाब घाटी में लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त मशीनरी उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया गया।

बैठक में सदस्यों द्वारा काजा के लोगों की मांग रखने पर निर्णय लिया गया कि काजा के अतिरिक्त उपायुक्त को आपदा प्रबन्धन के लिए उपायुक्त लाहौल स्पिति के माध्यम से प्रदान करने के बजाए सीधे तौर पर बजट उपलब्ध करवाया जाए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आईटीआई उदयपुर के प्रधानाचार्य का कार्यभार उपमण्डलाधिकारी उदयपुर को सौंपा जाए, क्योंकि वर्तमान में यह कार्यभार जिला कुल्लू के आईटीआई शमशी के प्रधानाचार्य के पास है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय अस्पताल रिकॉगपियो तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काजा को रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध करवाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य को अमलीजामा पहनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्लान हैड के अन्तर्गत 1770 करोड़ रू. तथा गैर योजना घटक के अन्तर्गत 2048 करोड़ रू. खर्च किए गए है इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सड़कों व पुलों की मुरम्मत के लिए 658 लाख रू. की राशि जारी की गई है।

भरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे वन मंत्री की मांग पर निर्णय लिया गया कि पांगी तथा भरमौर क्षेत्र के नौ रूटों पर मिनी बसें चलाई जाए।

बैठक में यह भी बताया गया कि केलांग स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपू को 14 बसें आबंटित की गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि लगातार भू-स्खलन से प्रभावित काजा के माना गांव के नालों के तटीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि भुगर्भीय सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसकी सिफारिशों के अनुसार जानमाल की हानि से बचने के लिए रोकने के लिए आवश्यक पग उठाए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि डीएफओ लाहौलघाटी विशेषकर मयाद तथा तिंगरिट क्षेत्र में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थान का चयन कर कार्य योजना बनाए। बैठक में लाहौल में चिन्हित स्थल पर विपणन मण्डी का निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में काजा-ग्राम्फु सड़क जो दयनीय स्थिति में है की मुरम्मत के बारे भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त लाहौल के यांगला पुल के कार्य पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुध-भावा सड़क के लिए वन्य जीव प्राधिकरण से वन स्वीकृति प्राप्त कर दी गई है तथा एफसीए के समक्ष इस मामले में तेजी लाई जा रही है। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने कार्यवाही का संचालन किया।

एचपीटीडीसी ने अगस्त 2017 तक अर्जित किया 682 लाख रुपये का लाभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के निदेशक मण्डल की 150वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने निगम के कर्मचारियें की निगम को वितीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की तथा उन्हें इस दिशा में और सुधार करने के लिए प्रयासरत रहने को कहा।

उन्होंने कहा कि एचपीटीडीसी की सम्पति की रेख-रखाव के लिए और प्रयास किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को प्रदेश की मेहमानवाजी का भरपूर आन्नद प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजित करने का एक अह्म स्त्रोत होने के कारण किसी भी राज्य का महत्पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। निगम कर्मचारियों को एचपीटीडीसी की बसों में यात्रा कर रहे पर्यटकों के साथ शालीनता तथा सदभाव से पेश आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि निगम ने वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान अगस्त, 2017 तक 682.27 लाख रुपये का कुल लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीटीडीसी के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों को बॉनस, दैनिकभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा कर्मचारियों की पदोन्नित की स्वीकृति भी प्रदान की।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक सौन्दर्य तथा विशेषकर धार्मिक व साहसिक पर्यटन पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थल है तथा स्की ढलाने व पैराग्लाईडिंग स्थल भी है जिसका समुचित दोहन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व धार्मिक पर्यटन को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एचपीटीडीसी के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि प्रति स्पर्धा के इस दौर में निगम की मौजूदा सम्पति का उन्नयन आवश्यक है तथा इससे पयटकों की संख्या में और बढ़ौतरी होगी। उन्होंने कहा कि निगम ने इस अवधि के दौरान निगम की सम्पति के जिर्णोद्धार, मुरम्मत तथा नवीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए है। मल्होत्रा ने कहा कि गत साढ़े चार वर्षो के दौरान 733 कर्मचारियों को पदोन्नत तथा 200 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई।

कौशल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए समिति गठित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सिरमौर जिले के काला-अम्ब के मां सरस्वती शैक्षणिक न्यास द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए एक विभागीय समिति का गठन किया है।

उच्च शिक्षा निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामांकित व्यक्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक, हि.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुल सचिव, हि.प्र. विश्विविद्यालय तथा हि.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय से तीन विषय विशेषज्ञ, नाहन के एसडीएम अथवा उनके द्वारा नामांकि व्यक्ति तथा हि.प्र. लोक निर्माण विभाग नाहन के अधिशाषी अभियन्ता समिति के सदस्य होंगे। निदेशक हि.प्र. उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक (कॉलेज) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ एक महीने के भीतर प्रस्तुत करेंगी

रत्न कभी खंडित नहीं होता। अर्थात विद्वान व्यक्ति में कोई साधारण दोष होने पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। .....चाणक्य

सम्पादकीय

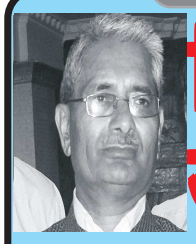

किन मुद्दों पर लड़ा जायेगा यह चुनाव

प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवम्बर में होने तय हैं। इस चुनाव में भी मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच ही रहेगा यह भी तय है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस को पंजाब के अतिरिक्त कोई सफलता नही मिली है। इसी सफलता का परिणाम है कि आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री ओर लोकसभा अध्यक्ष तक देश के चारों शीर्ष पदों पर सत्तारूढ़ भाजपा का कब्जा है। भाजपा को यह सफलता क्यों और कैसे मिली है। इस पर यहां चर्चा का कोई औचित्य नही है। लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण है कि इस सफलता से देश को क्या है। किसी भी सरकार की कसौटी उसकी आर्थिक और सामाजिक नीतियां होती है और इन्ही नीतियों की समीक्षा किसी भी चुनाव का केन्द्रिय मुद्दा होना चाहिये। इस दृष्टि से आर्थिक नीति पटल पर नोटबंदी मोदी सरकार का एक प्रमुख फैसला रहा है। यह फैसला लेने के जो भी आधार रहे हैं और इस फैसलें से जो भी उपलब्धियां अपेक्षित थी वह सब आधारहीन साबित हुई है। क्योंकि जब पुराने 99% नोट सरकार के पास रिर्जब बैंक में वापिस पहुंच गये हैं और इन्हें नये नोटों से बदलना पड़ा है तो इसमें सरकार के अतिरिक्त और किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। सरकार ने पहले पुराने नोट छापने और उन्हे उपभोक्ता तक पहुंचाने में निवेश किया और अब नये नोटों के लिये वही सब कुछ करना पड़ा। इस फैसले से कालेधन को लेकर भी जो धारणा – प्रचार देश में पहले चल रही थी वह भी पूरी तरह सही साबित नही हुई है। इस तरह जब यह मूल फैसला ही असफल हो गया है तो इसके बाद फैसलों के भी वांच्छित परिणाम मिलना संभव नही है और यही सब कुछ हर संपति को आधार से जो जोड़ने जी एस टी लागू करने हर काम डिजिटल प्रणाली से करने आदि के फैसलों से हुआ है। इसी सबका परिणाम है पेट्रोल – डीजल की कीमतें बढ़ना और उससे हर चीज का मंहगा होना। सरकार के इन फैसलों से जनता को असुविधा हुई है रोष भी पनप रहा है क्योंकि इन सब फैसलों का लाभार्थी नीजिक्षेत्र के कुछ अंबानी – अदानी जैसे बड़े उद्योग घराने ही हुए है।

मोदी सरकार देश के युवाओं को मेक – इन – इण्डिया का एक सूत्र दिया है लेकिन इस सूत्र की व्यवहारिकता आज पूरी तरह सवालों में आ खड़ी हुई है। क्योकि सरकार के इस संद्धर्भ में लिये गये फैसलों की हकीकत इसके एकदम उल्ट है। बुलेट ट्रैन के फैसलें को कार्यन्वित करेगा जापान। यह कहा गया है कि इस पर होने वाला करीब 1.50 लाख करोड़ का निवेश मामूली ब्याज पर जापान भारत को देगा और इसे 50 वर्षो में जापानी मुद्रा में वापिस किया जायेगाा। उस समय रूपये की कीमत जापानी मुद्रा के मुकाबले में क्या रहेगी? क्या उस समय यही एक लाख करोड़ पचास लाख करोड़ नही बन जायेगा। क्योंकि जो ऋण भारतीय मुद्रा में लिया जाता है और उसे जब ऋण देने वाले देश की मुद्रा में वापिस किया जाता है तब सारा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिये ऐसे बड़े फैसले वर्तमान की व्यवहारिकता को देखकर लिये जाने चाहिये। आज सरदार पटेल की मूर्ति हम चीन से बनवा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लिये स्वीडन और मेक – इन – इण्डिया का ''लोगो'' तक तो हम खुद न बना कर स्वीटज़रलैण्ड से बनवा रहे हैं। प्रधानमन्त्री की अपनी बुलेट प्रूफ कार ही जमर्नी की बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे फैसले ऐसे है जहां सरकार स्वयं अपनी ही मेक – इन – इण्डिया की धारणा के खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि अभी देश इस तरह के फैसलों के लिये पूरी तरह तैयार नही है लेकिन सरकार का पूरा जोर इन फैसलों को सही प्रचारित – प्रसारित करने का एक तरह से अभियान छेड़ा गया है। जबकि आर्थिक फैसलों की कसौटी मंहगाई और बेरोजगारी का कम होना ही होता है। माना जा सकता है कि बेरोजगारी कम होने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मंहगाई तो तुरन्त प्रभाव से रूकनी चाहिये जो लगातार बढ़ती जा रही है।

इसलिये आज जब जनता के पास फिर से सरकार चुनने का अवसर है तो उसे उसके सामने आने वाले उम्मीदवारों से इन सवालों पर खुलकर जवाब मांगना चाहिये। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कैसे उसका प्रतिनिधि जनता पर बिना कोई नया टैक्स लगाये और सरकार पर कर्ज का बोझ डाले बिना कैसे मंहगाई और बेरोजगारी की समस्याओं को हल करेगा। क्योंकि आज प्रदेश पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुका है। एक लम्बे अरसे से कोई बड़ा उद्योग प्रदेश में नही आया है। जिस प्रदेश को एक विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित – प्रसारित किया गया था आज इन्ही विद्युत परियोजनाओं के कारण प्रदेश का आर्थिक सन्तुलन बुरी तरह बिगड़ गया है। क्योंकि प्रदेश में विद्युत के उत्पादन में कार्यरत नीजिक्षेत्र से सरकार को मंहगी दरों पर अनुबन्धों के कारण बिजली खरीदनी पड़ रही है लेकिन मुनाफा तो दूर उन्ही दरों पर आगे बिक नही रही है। इसी के कारण सरकार – विद्युत बोर्ड के अपने स्वामित्व वाली परियोजनाओं में हर वर्ष हज़ारों – हज़ार घन्टो का शट डाऊन चल कर इनमें उत्पादन बन्द कर रखा गया है। यह स्थिति पिछले एक दशक से अधिक समय से चली आ रही है लेकिन सरकारी तन्त्र इस संद्धर्भ में आयी शिकायतों के वाबजूद इस ओर कोई कारवाई नही कर रहा है। आज भाजपा जिस तरह से चुनावी मुद्दे लेकर आ रही है उनमें भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उछाला गया है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोग है और इस पर अंकुश लगाना चाहिये इसमे कोई दो राय नही हो सकती। लेकिन यहां भाजपा को यह बताना होगा कि उसने अपने पहले के दोनो ही शासनकालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया? क्योंकि पिछला रिकार्ड यह प्रमाणित करता है कि भाजपा ने अपने ही सौंपे आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नही की है इसके दस्तावेजी प्रणाम आने वाले दिनों मे हम पाठकों के सामने रखेंगे। इसलिये आज प्रदेश की जनता से यह अपेक्षा है कि वह इस चुनाव में पार्टीयों के ऐजैण्डे को प्रमुखता और गंभीरता देने की बजाये उन आर्थिक सवालों पर चिन्तन करें जो हमने पाठकों के सामने रखें है और फिर अपने समर्थन का फैसला ले।

हिमाचल में तीव्र जल विद्युत उत्पादन के लिए नवीन कार्य-योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विद्यमान अपार जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन के लिए एक महत्वाकांक्षी, नवीन एवं पर्यावरण मित्र कार्य योजना तैयार की है। प्रदेश में 27436 मैगावाट की सूक्ष्म जल विद्युत सम्भावना में से 10351 मैगावाट का दोहन इस क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न जानी – मानी एजेंसियों की सक्रिय सहभागिता से पहले ही कर लिया गया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों से निपटने व निवेशकों की सुविधा के लिए नीति प्रावधानों को सरल बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिला स्तर पर एक समय सीमा के भीतर विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया गया है। निर्माताओं को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों के बजाए सीधे तौर पर सम्बन्धित उपायुक्तों को आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।

प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में सुरक्षा तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने ऊर्जा निदेशालय के तत्वावधान में सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्राधिकरण का सृजन किया है। बांधों की सुरक्षा तथा संचालन प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य खरीद एवं प्रबन्धन के लिए दिशा – निर्देशों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

संचालित परियोजनाओं के अनिवार्य निरीक्षण को सुनिश्चित बनाया गया है तथा मानसून के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली को भी लागू किया जा रहा है। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी व निर्माताओं द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा के लिए एक निगरानी इकाई भी स्थापित की गई है।

प्रदेश सरकार ने तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल बनाई है तथा ऊर्जा निदेशालय को प्रक्रिया के संचालन व 1000 करोड़ रूपये से कम की परियोजनाओं को तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। गत साढ़े चार वर्षो के दौरान अभी तक लगभग 700 मैगावाट क्षमता की 167 परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान 2067 मैगावाट की कुल क्षमता वाली लगभग 31 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया गया तथा 10 मैगावाट घानवी, 800 मैगावाट कोलडैम, 412 मैगावाट रामपुर, सतलुज नदी पर 130 मैगवाट की कशरंग, ब्यास नदी पर 520 मैगावाट की पार्वती चरण – 3 तथा रावी नदी पर 36 मैगावाट की छांजु परियोजनाएं सरकार द्वारा आरम्भ की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जहां एक ओर प्रदेश के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से 300 मैगावाट क्षमता वाली कम से कम 22 पर्यावरण मित्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की पहल की है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बहने वाली नदियों, विशेषकर ब्यास, रावी तथा पब्बर नदियों की क्षमता के दोहन की सम्भावनाओं को तीव्रता से तलाश रहा है। कुल्लू जिला के रायसन में प्रायोगिक आधार पर 18 सूक्ष्म परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व बैंक ने पहले ही इस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध करवाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

राज्य बिजली बोर्ड ने पहले ही 487.45 मैगावाट क्षमता वाली

लगभग 22 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू कर दिया है तथा 100 मैगावाट ऊहल चरण – 2 परियोजना का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है जिसका प्रायोगिक आधार पर शीघ्र परिचालन आरम्भ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड की कार्य क्षमता तथा विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए चम्बा के देवीकोठी (16 मैगावाट) तथा हाएल (18 मैगावाट) का निर्माण कार्य बिजली बोर्ड को सौंपा है।

राज्य सरकार ने बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न पग उठाए हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से 2890 करोड़ रूपये का ऋण लिया है ताकि बोर्ड उच्च ब्याज दरों पर पहले लिए गए ऋणों की अदायगी कर सके।

राज्य सरकार ने परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के उपयुक्त पुनर्वास के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा इन परियोजनाओं के शुरू होने के उपरान्त एक प्रतिशत अतिरिक्त नि:शुल्क विद्युत की बिक्री का प्रावधान किया है ताकि इससे प्राप्त राजस्व को प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रदेश इस प्रकार की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है तथा सत्र 2012 – 13 से अभी तक लगभग 6.74 करोड़ रूपये पात्र परिवारों को प्रदान किए जा चुके हैं। राज्य सरकार परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को प्रत्येक को 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली भी प्रदान कर रही है।

राज्य सरकार ने नि:शुल्क एवं इक्विटी पॉवर की बिक्री से 3345 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है तथा इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि चिन्हित जल विद्युत सम्भावनाओं का दोहन समय सीमा के भीतर किया जा सके। वह दिन दूर नहीं जब राज्य पूरे देश की बढ़ती बिजली की मांग को अकेले पूरा करने में सक्षम होगा तथा प्रदेश देश में 'ऊर्जा राज्य' के रूप में उभरेगा।

दूरदर्शन के 58 साल

दूरदर्शन का आज भी कोई सानी नहीं है

टेलीविजन का आविष्कार यूँ तो जॉन एल बिलियर्ड ने 1920 के दौर में ही कर दिया था। लेकिन भारत में यह टीवी तब पहुंचा जब 15 सितम्बर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने दिल्ली में एक प्रसारण सेवा दूरदर्शन का उद्घाटन किया। हालांकि तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह दूरदर्शन, यह टीवी आगे चलकर जन जन की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। आज यह टीवी रोटी कपड़ा और मकान के बाद लोगों की चौथी ऐसी जरुरत बन गया है कि जिसके बिना जिंदगी मुश्किल और सूनी सी लगती है। प्रदीप सरदाना

अब वही दूरदर्शन अपने जीवन के 58 बरस पूरे कर चुका है. इतने बरसों में दूरदर्शन का, टीवी का अपने देश में इतना विकास हुआ है कि इसे देखना जीवन की एक आदत ही नहीं जरुरत बन गया है। हालांकि शुरूआती बरसों में दूरदर्शन का विकास बहुत धीमा था। शुरूआती बरसों में इस पर आधे घंटे का नाम मात्र प्रसारण होता था। पहले इसे स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल टेलीविजन के रूप में शुरू किया गया। लेकिन इसका 500 वाट का ट्रांसमीटर दिल्ली के मात्र 25 किमी क्षेत्र में ही प्रसारण करने में सक्षम था। तब सरकार ने दिल्ली के निम्न और माध्यम वर्गीय क्षेत्र के 21 सामुदायिक केन्द्रों पर टीवी सेट रखवाकर इसके प्रसारण की विशेष व्यवस्था करवाई थी। ऐसे में तब दूरदर्शन से कोई बड़ी उम्मीद भला कैसे रखी जा सकती थी। हालाँकि जब 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन पर समाचारों का एक घंटे का नियमित हिंदी बुलेटिन आरम्भ हुआ तब दूरदर्शन में लोगों की कुछ दिलचस्पी बढती दिखाई दी। इसके बाद दूरदर्शन पर 26 जनवरी 1967 को किसानों को खेती बाड़ी आदि की खास जानकारी देने के लिए दूरदर्शन पर 'कृषि दर्शन' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी दौरान दूरदर्शन पर नाटकों का प्रसारण भी शुरू किया गया। लेकिन दूरदर्शन की लोकप्रियता में बढ़ोतरी तब हुई जब इसमें शिक्षा और सूचना के बाद मनोरंजन भी जुड़ा।

असल में जब 2 अक्तूबर 1972 को दिल्ली के बाद मुंबई केंद्र शुरू हुआ तो मायानगरी के कारण इसका फिल्मों से जुड़ना स्वाभाविक था। मनोरंजन के नाम पर दूरदर्शन पर 70 के दशक की शुरुआत में ही एक एक करके तीन शुरुआत हुई। एक हर बुधवार आधे घंटे का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रहार शुरू किया गया। दूसरा हर रविवार शाम एक हिंदी फीचर फिल्म का प्रसारण शुरू हुआ। साथ ही एक कार्यक्रम 'फूल खिले हैं गुलशन गुलशन' भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री तब्बसुम फिल्म कलाकारों के इंटरव्यू लेकर उनकी जिंदगी की फिल्मी बातों के साथ व्यक्तिगत बातें भी दर्शकों के सामने लाती थीं। तब देश में फिल्मों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ चुकी थी। लेकिन सभी के लिए सिनेमा घर जाकर सिनेमा देखना संभव नहीं था, ऐसे में जब यह सब दूरदर्शन पर आया तो दर्शकों की मुराद घर बैठे पूरी होने लगी। यूँ यह वह दौर था जब 1970 में देश भर में मात्र 24838 टीवी सेट थे। जिनमें सामुदायिक केन्द्रों में सरकारी टीवी सेट के साथ कुछ अधिक संपन्न व्यक्तियों के घरों में ही टीवी होता था। ऐसे में तब अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग भी अपने किसी संपन्न पडोसी या रिश्तेदार के यहाँ जाकर बुधवार का चित्रहार और रविवार की फिल्म देखने का प्रयास करते थे।

सीरियल युग से आई टीवी में क्रांति

समाचार, चित्रहार और फिल्मों के बाद दूरदर्शन में दर्शकों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब दूरदर्शन पर सीरियल युग का आरम्भ हुआ। यूँ तो दूरदर्शन पर कभी कभार सीरियल पहले से ही आ रहे थे। लेकिन सीरियल के इस नए मनोरंजन ने क्रांति का रूप तब लिया जब 7 जुलाई 1984 को 'हम लोग' का प्रसारण शुरू हुआ। निर्मात्री शोभा डॉक्टर, निर्देशक पी कुमार वासुदेव और लेखक मनोहर श्याम जोशी के 'हम

लोग' ने दर्शको पर अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि हमारे सामाजिक परिवेश, दिनचर्या और आदतों तक में यह बड़ा परिवर्तन साबित हुआ, जिससे हम सब की दुनिया ही बदल गयी। 'हम लोग' के कुल 156 एपिसोड प्रसारित हुए लेकिन इसका आलम यह था कि जब इसका प्रसारण होता था तब कोई मेहमान भी किसी के घर आ जाता था था तो घर वाले उसकी परवाह न कर अपने इस सीरियल में ही मस्त रहते थे। लोग शादी समारोह में जाने में देर कर देते थे लेकिन 'हम लोग' देखना नहीं छोड़ते थे। 'हम लोग' और दूरदर्शन की लोकप्रियता का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि सन 1970 में देश में जहाँ टीवी सेट की संख्या 24838 थी 'हम लोग' के बाद 1984 में वह संख्या 36,32,328 हो गयी।

'हम लोग' का दर्शकों पर जादू देख दूरदर्शन ने 1985 में ही हर रोज शाम का दो घंटे का समय विभिन्न सीरियल के नाम कर दिया। जिसमें आधे आधे घंटे के 4 साप्ताहिक सीरियल आते थे। सभी सीरियल को 13 हफ्ते यानी तीन महीने का समय दिया जाता था। उसके बाद वह जगह किसी नए सीरियल को दे दी जाती थी। सिर्फ किसी उस सीरियल को कभी कभार 13 और हफ्तों का विस्तार दे दिया जाता था, जो काफी लोकप्रिय होता था या फिर जिसकी कहानियां कुछ लम्बी होती थी। इस दौरान दूरदर्शन पर बहुत से ऐसे सीरियल आये जिन्होंने दर्शकों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। लेकिन दूरदर्शन की इस लोकप्रियता को तब और भी पंख लग गए जब दूरदर्शन ने 1987 में 'रामायण' महाकाव्य पर सीरियल शुरू किया। फिल्म निर्माता रामानंद सागर द्वारा निर्मित निर्देशित 'रामायण' सीरियल ने टीवी की लोकप्रियता को एक दम एक नया शिखर प्रदान कर दिया। जब रविवार सुबह 'रामायण' का प्रसारण होता था तो सभी सुबह सवेरे उठकर, नहा धोकर टीवी के सामने 'रामायण' देखने के लिए ऐसे बैठते थे जैसे मानो वे मंदिर में बैठे हों। 'रामायण' के उस प्रसारण के समय सभी घरों में टीवी के सामने होते थे तो घरों के बाहर सुनसान और कर्फ्यू जैसे नजारे दिखते थे। बाद में 'रामायण' की लोकप्रियता से प्रभावित होकर दूरदर्शन ने अगले बरस एक और महाकाव्य 'महाभारत' का प्रसारण शुरू कर दिया। फिल्मकार बीआर चोपड़ा द्वारा बनाए गए इस सीरियल ने भी जबरदस्त लोकप्रियता पायी।

दूरदर्शन के पुराने लोकप्रिय सीरियल को याद करें तो हम लोग, रामायण और महाभारत के अतिरिक्त ऐसे बहुत से सीरियल रहे जिन्होंने सफलता, लोकप्रियता का नया इतिहास लिखा। जैसे यह जो है जिंदगी, कथा सागर, बुनियाद, वागले की दुनिया, खानदान, मालगुडी डेज, करमचंद, एक कहानी, श्रीकांत, नुक्कड़, कक्का जी कहिन, भारत एक खोज, तमस, मिर्जा गालिब, निर्मला, कर्मभूमि, कहाँ गए वो लोग, द सोर्ड ऑफ टीपू सुलतान, उड़ान, रजनी, चुनौती, शांति, लाइफ लाइन, नींव, बहादुर शाह जफर, जूनून, स्वाभिमान, गुल गुलशन गुलफाम, नुपूर, झरोखा, जबान संभाल के, देख भाई देख, तलाश और झांसी की रानी आदि।

एक ही चैनल ने बरसों तक बांधे रखा

यह निश्चय ही सुखद और दिलचस्प है कि आज चाहे देश में कुल मिलाकर 800 से अधिक उपग्रह-निजी चैनल्स का प्रसारण हो रहा है। जिसमें मनोरंजन के साथ समाचार चैनल्स भी हैं तो संगीत, सिनेमा, खेल स्वास्थ्य, खान पान, फैशन, धार्मिक, आध्यात्मिक और बच्चों के चैनलस भी हैं तो विभिन्न भाषाओँ और प्रदेशों के भी। लेकिन एक समय था जब अकेले दूरदर्शन ने यह सारा जिम्मा उठाया हुआ था। दूरदर्शन का एक ही चैनल समाचारों से लेकर मनोरंजन और शिक्षा तक की सभी कुछ दिखाता था। जिसमें किसानों के लिए भी था बच्चों और छात्रों के लिए भी, नाटक और फिल्में भी थी तो स्वास्थ्य और खान पान की जानकारी के साथ कवि सामेलन भी दिखाये जाते थे और नाटक भी। मौसम का हाल होता था और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी। क्रिकेट, फुटबाल सहित विभिन्न मैच का प्रसारण भी होता था तो स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का सीधा प्रसारण भी। धरती ही नहीं अन्तरिक्ष तक से भी सीधा प्रसारण दिखाया जाता था जब प्रधानमन्त्री के यह पूछने पर कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तब भारतीय अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के 'सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा, कहने पर पूरा देश गर्व से रोमांचित हो गया था। बड़ी बात यह है कि दूरदर्शन के इस अकेले चैनल ने सही मायने में सन 1990 के बाद के कुछ बरसों तक भी अपना एक छत्र राज बनाए रखा। यूँ कहने को दूरदर्शन का एक दूसरा चैनल 17 सितम्बर 1984 को शुरू हो गया था। लेकिन सीमित अवधि और सीमित कार्यक्रमों वाला यह चैनल दर्शकों पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाया जिसे देखते हुए इसे कुछ समय बाद बंद कर देना पड़ा। बाद में 2 अक्तूबर 1992 में जहाँ जी टीवी से उपग्रह निजी हिंदी मनोरंजन चैनल की देश में पहली बड़ी शुरुआत हुई वहां 1993 में दूरदर्शन ने मेट्रो चैनल की भी शुरुआत की। तब निजी चैनल्स के साथ मेट्रो चैनल को भी बड़ी सफलता मिली और दर्शकों को नए किस्म के नए रंग के सीरियल आदि काफी पसंद आये। लेकिन उसके बाद देश में सभी किस्म के चैनल्स की बाढ़ सी आती चली गयी। इससे दूरदर्शन को कई किस्म की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहली चुनौती तो यही रही कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते दूरदर्शन के सामजिक जिम्मेदारियां हैं। दूरदर्शन मनोरंजन के नाम पर निजी चैनल्स की तरह दर्शकों को कुछ भी नहीं परोस सकता।

दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू भी कहती हैं-यह ठीक है कि दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रोडकास्टर है लेकिन मैं समझती हूँ कि यह सब होते हुए भी दूरदर्शन अपनी भूमिका अच्छे से निर्वाह कर रहा है। दूरदर्शन का आज भी दर्शकों में अपना अलग प्रभाव है, दूरदर्शन अपने दर्शकों को साफ सुथरा और उद्देश्य पूर्ण मनोरंजन तो प्रदान कर ही रहा है लेकिन दर्शकों को जागरूक करने की भूमिका में दूरदर्शन सभी से आगे है। बड़ी बात यह है देश में कुछ निजी चैनल्स मनोरंजन और समाचारों के नाम पर जो सनसनीखेज वातावरण तैयार करते हैं दूरदर्शन हमेशा इससे दूर रहकर स्वस्थ और सही प्रसारण को महत्व देता है। हाँ दूरदर्शन के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूरदर्शन के इस 58 वें स्थापना दिवस पर मैं सभी को यह विश्वास दिलाती हूँ कि आज दूरदर्शन अपनी सभी किस्म की चुनौतियों से निबटने के लिए स्वयं सक्षम है। आज हमारे पास विश्व स्तरीय तकनीक है हम दुनियाभर में जाकर अपने एक से एक कार्यक्रम बनाते हैं और दिखाते हैं निजी चैनल जिन मुद्दों पर उदासीन रहते हैं वहां हम उस सब पर बहुत कुछ दिखाते हैं, जैसे किसानों पर, स्वच्छता पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। कला पर संस्कृति पर। आज दूरदर्शन के देश में कुल 23 चैनल्स हैं जिनमें 16 सेटेलाइट्स चैनल हैं और 7 नेशनल चैनल्स। जिससे दूरदर्शन आज महानगरों से लेकर छोटे नगरों, कस्बों और गाँवों तक पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हमारे कार्यक्रम तकनीक और कंटेंट दोनों में उत्तम हैं। इस सबके बाद भी यदि कहीं कोई कमी मिलती है तो हम उसे दूर करेंगे। समय के साथ अपने कार्यक्रमों की निर्माण गुणवत्ता में जो आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, उसे भी हम करेंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटेंगे और दर्शको का दूरदर्शन में भरोसा भी कायम रखेंगे।

दूरदर्शन में दर्शकों का भरोसा कायम रहे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरा तो दूरदर्शन से अपना भी व्यक्तिगत लगाव है। पहला तो इसलिए ही कि मैं भी देश के लाखों करोड़ों लोगों की तरह बचपन से दूरदर्शन को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसके साथ दूरदर्शन से मेरा विशेष और अलग लगाव इसलिए भी है कि मैंने ही देश में सबसे पहले दूरदर्शन पर नियमित पत्रकारिता शुरू की। सन 1980 के दशक के शुरुआत में ही मुझे इस बात का अहसास हो गया था कि दूरदर्शन जल्द ही घर का एक सदस्य बन जाएगा। जब दूरदर्शन पर 'हम लोग' से भी पहले 'दादी माँ जागी' नाम से देश का पहला नेटवर्क सीरियल शुरू हुआ तो मैंने उसकी चर्चा देश के विभिन्न हिस्सों में दूर दराज तक होते देखी। मुझे लगा कि एक सीरियल एक ही समय में पूरे देश में यदि देखा जाएगा तो यह टीवी मीडिया क्रांति ला देगा। तब हम कोई फिल्म देखते थे तो वह अलग अलग समय में अलग अलग दिनों में देखते थे मगर रात 8 या 9 बजे राष्ट्रीय प्रसारण वाला सीरियल एक साथ एक ही समय में पूरा देश देख लेता था। उसके बाद उसमें दिखाए दृश्य अगले दिन सभी की चर्चा का विषय बने होते थे। यह ठीक है कि अब अलग अलग सैंकड़ों चैनल्स आने से स्थितियों में बदलाव हुआ है लेकिन दूरदर्शन ने देश को एक साथ जोड़ने, लोगों को जागरूक करने, शिक्षित करने और उन्हें मनोरंजन प्रदान करने का जो कार्य किया है उसका आज भी कोई सानी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने की जिला मण्डी में 35 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाएं लोकार्पित

शिमला/शैल। सुन्दरनगर में आरम्भ की गई 'स्मार्ट अण्डरग्राऊण्ड डस्टबिन योजना' स्थापित करेगी प्रदेश में स्वच्छता के नए आयाम

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सचिवालय से मण्डी जिला के सन्दरनगर तथा नाचन क्षेत्रों के लिए

35 करोड़ रुपये की लागत के विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण तथा आधारशिलाएं रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में हमेशा ही विकास के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित बनाया है जो प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रगति मानकों से साफ झलकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक भाग में पर्यटकों को आकर्षित करने की आपार सम्भावनाएं है जिसका लोगों के सहयोग द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों व पर्यटन गणतव्य पर नागरिक सुविधाएं तथा स्वच्छता बनाए रखकर दोहन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्दरनगर में 4.46 करोड़ रुपये की स्मार्ट भूमिगत कुड़ादान योजना आरम्भ करने से प्रदेश के शहरों तथा कस्बों में स्वच्छता के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के माध्यम से पहाड़ों की सुन्दरता को बनाए रखने व बढाने में सहायता करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण सुन्दरनगर के 13 वार्डो के विभिन्न स्थानों पर 40 भूमिगत कुडेदान स्थापित किए जाएंगे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके पूर्व कार्यकाल की गई पहल के फलस्वरूप सुकेत शॉपिंग परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसके बनने से सुन्दरनगर के नागरिकों को सुविधाएं तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 2.31 करोड़ रुपये से निर्मित परिसर में बहुउदेशीय सभागार के अतिरिक्त यात्री निवास भी होगा जिसमें सुन्दरनगर आने वाले आगन्तुकों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी तथा इस परिसर में 74 दुकानों व एक रेस्तरां की सुविधा होंगी।

मुख्यमंत्री ने जिला मण्डी को जिला बिलासपुर से जोड़ने वाले धवाल (सलापड़-ततापानी) से जोड़ने के लिए सतलुल नदी पर 20.29 करोड़ रुपये की लागत से मोटर योग्य पुल की आधारशिला रखी। इस पुल के बनने से जिला मण्डी की पांच पंचायतों तथा जिला बिलासपुर की तीन पंचायतों को लाभ मिलेगा।

वीरभद्र सिंह ने राजकीय डिग्री कॉलेज देहर के भवन की आधारशिला रखी जिस पर 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज में कक्षाओं को आरम्भ करने की घोषणा भी की।

मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सुन्दरनगर के लिए चार विकासात्मक परियोजनाएं उपहार दी है जो क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होंगी।

मुख्यमंत्री ने मण्डी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए 1.49 करोड़ रुपये की लागत से खण्डल-नन्दी सड़क पर निर्मित पुल और 1.55 करोड़ रुपये की लागत से खेयोड़ के सैंज बाड़ा सड़क पर सैंज पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने खेयोड़ की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहाल के अतिरिक्त भवन की भी आधारशिला रखी, जिस पर 36.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नन्दीपुल के निर्माण से क्षेत्र की पांच पंचायतें जिनमें तान्दी, नन्दी, दरान, सरवा और सैंज की 10 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी और सैंज पुल से सैंज, बाड़ा तथा पाराबारा पंचायतों की 7000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

विधायक टेकचन्द ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास का श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है, जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री ने परवाणु में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को सौंपी फ्लैटों की चाबियां

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के परवाणु में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए निर्मित किए गए फ्लैटों की चाबियां वितरित की। फ्लैटों के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी निवासियों के स्थाई जीवन

के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है। जैसा की परवाणु, हिमाचल के लिए प्रवेश द्वार है, इसलिये शहर को आंगतुकों के लिये एक स्वच्छ छवि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर सम्भावनाएं तलाशने के लिए प्रवासियों ने आमतौर पर अपने गांवों का त्याग कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इन लोगों का भूमि अथवा संपति पर कोई दावा नहीं है। भारतीय शहरों के विस्तार से मलिन बस्तियों को खाली करना तथा इनके विध्वंस में वृद्धि हुई है और समार्ट शहर मिशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके संवारने का कार्य किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार के लिये केन्द्रों का सृजन करना है।

उन्हांने फहड़ी वालों (स्ट्रीट वेन्डर्ज) के लिए 200 बूथों (कियोस्क) की भी आधारशिला रखी जिसके निर्माण पर 6.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हिमुडा के दो वाणिज्यिक परिसरों की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने परवाणु में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को सौंपी फ्लैटों की चाबियां।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के परवाणु में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए निर्मित किए गए फ्लैटों की चाबियां वितरित की। फ्लैटों के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी निवासियों के स्थाई जीवन के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है। जैसा की परवाणु, हिमाचल के लिए प्रवेश द्वार है, इसलिये शहर को आंगतुकों के लिये एक स्वच्छ छवि देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर सम्भावनाएं तलाशने के लिए प्रवासियों ने आमतौर पर अपने गांवों का त्याग कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इन लोगों का भूमि अथवा संपति पर कोई दावा नहीं है।

भारतीय शहरों के विस्तार से मलिन बस्तियों को खाली करना तथा इनके विध्वंस में वृद्धि हुई है और स्मार्ट शहर मिशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके संवारने का कार्य किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार के लिये केन्द्रों का सृजन करना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए झोंपड़ी-वासियों के लिए आवास की सुविधाओं के सृजन की पहल एक सराहनीय कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक सड़कों के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जल्द ही हस्तांतरित की जाएगी।

उन्हांने फहड़ी वालों (स्ट्रीट वेन्डर्ज) के लिए 200 बूथों (कियोस्क) की भी आधारशिला रखी जिसके निर्माण पर 6.30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 88 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हिमुडा के दो वाणिज्यिक परिसरों की भी आधारशिला रखी।

विधायकों को जमीन देने का निर्णय गलतः धूमल

हमीरपुर/शैल। भूमिहीनों को भूमि देने वाला चुनाव घोषणा पत्र का वायदा भूल विधायकों को कई बीघे जमीन देने का सरकार का निर्णय आलोचनात्मक। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार के बीते कल के केबिनेट बैठक के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए यह बात कही। पांच वर्ष तक सरकार भूमिहीनों, गृह हीनों को दो-दो बिस्वे जमीन देने का चुनावी घोषणा पत्र का वायदा भूल कर विधायकों को कई बीघे जमीन देने का निर्णय ले रही है। वह जनता के बीच आलोचना और मजाक का विषय तो बनेगा ही साथ में विधायकों को अपमानित करने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस समय की गयी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी। फिर ऐसे हास्यस्पद निर्णय केवल मात्र विधायकों और पूर्व विधायकों की छवि को खराब करेंगे।

प्रो. धूमल ने कहा कि मंत्रीमंडल की बैठक से पहले कई वरिष्ठ अधिकारी छूट्टी ले लेते हैं ताकि गलत फाइल पर उनके दस्तखत न हों। हस्ताक्षर करने से भी अधिकारी बच रहे हैं, वह जानते हैं कि निर्णय जो गलत होंगे उनका अंततः उनको ही भुगतान करना पड़ेगा, और उनको ही गलत काम की सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ अधिकारी अति उत्साह में आकर आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन करवा रहे हैं, हमने पहले ही कहा है ऐसे अधिकारियों को इन कार्यों को पूरा करने के लिए बाद में अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा, उनको अपनी जेब से पैसा लगा कर इन कार्यों को पूरा करना पड़ेगा।

प्रो. धूमल ने कहा की ज्यूँ-ज्यूँ चुनाव का समय और आचार सहिंता लगने का समय नजदीक आ रहा है, कांग्रेस सरकार बोखलाहट में अनाप शनाप घोषणाएं कर रही है। मंत्री मंडल के निर्णय मजाक का विषय बन गये है।सरकार अपनी तरफ से लोक -लुहावने निर्णय लेती हैं लेकिन जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिन कर्मचारियों को पांच साल लगातार प्रताड़ित किया, तंग रखा, जिनको समय पर वेतन नहीं मिला, समय पर दिहाड़ी नहीं मिली और समय पर डीए की किश्त नहीं मिली, अब उनको बहुत कुछ देने की घोषणा करना केवल अपने आप को बेवकूफ बनाने के सिवाए और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जिन नौजवानों को धोखा देकर चुनाव में कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनको पांच साल तक अँधेरे में रख कर अब लालच देना इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। केवल झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। नए-नए संस्थानों की घोषणा हो रही है, बिना बजट के शिलान्यास हो रहे हैं, आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन हो रहा है। हर बार केबिनेट की बैठक के बाद खबर आ जाती है कि नौकरियों का पिटारा खुला, लेकिन पिटारे में से कितनी नौकरियाँ निकली हैं और कितनों को मिली हैं? इन सब बातों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि प्रदेश सरकार को पता है। वह सत्ता में वापिस नहीं आयेंगे इसीलिए अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। जनता भी इनकी झूठी घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती।

वीरभद्र सिंह ने किया हिमाचल की जनता से धोखाः अनुराग ठाकुर

हमीरपुर/शैल। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं के उस ब्यान पर चुटकी ली है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं।

हमीरपुर सांसद ने कहा 'मुख्यमंत्री के स्वार्थी और उदासीन रवैये के कारण कांग्रेस सरकार के वर्तमान शासन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2013 में जब से उन्होंने पद सम्भाला है वो और उनके परिवार के सदस्यों का नाम तब से ही भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आ रहा है। मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के आम आदमी को अपने टैक्स से दिए गए पैसे जो की प्रदेश के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए उसका मुख्यमंत्री से हिसाब माँगने का पूरा अधिकार है। जो पैसे जनता के विकास के लिए खर्च होने चाहिए थे। उन पैसों का फार्महाउस खरीद का मुख्यमंत्री किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं ये जवाब जानने का भी जनता को पूरा हक है।

इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि ''एक राज्य जिसे अतीत में करीब 85 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और नंबर 1 की स्थिति को रैंकिंग में 24 वें स्थान पर आ गया है। हर दूसरे दिन आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबर सुनते हैं और मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाओं को छोटी और आम घटना मानते हैं। हिमाचल की जनता ने उन्हें राज्य के विकास के लिए वोट दिया था मगर 5 साल वो हिमाचल की जनता के साथ धोखा करते हुए सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में व्यस्त रहे, और उनकी लोकप्रियता का यही कारण है की आज प्रदेश का बच्चा बच्चा उनके काले कारनामों के बारे में बात कर रहा है और उन पर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बजाए पीछे ढकेलने का आरोप लगा रहा है।

हिमाचल सरकार का ऐतिहासिक क़दम

प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं की मददगार बनी

बेरोज़गारी भत्ता योजना-2017

श्री वीरभद्र सिंह
माननीय मुख्य मंत्री, हि.प्र.

हिमाचल सरकार बेरोज़गार युवाओं के साथ

- आवेदकों को ₹1000 प्रतिमाह
- 50% विकलांगों को ₹1500 प्रतिमाह
- भत्ता दो वर्ष के लिए देय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान

पात्रता :

- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी
- रोज़गार कार्यालय में एक वर्ष से पंजीकृत
- आयु 20-35 वर्ष • न्यूनतम 10+2 पास
- पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम
- बेरोज़गारी बारे स्वयं प्रमाणित घोषणा-पत्र
- किसी सरकारी, निजी रोज़गार या स्वरोज़गार में न हो
- किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत न हो
- वर्तमान में कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो

18-9-2017 तक 16936 युवाओं को ₹3.46 करोड़ से अधिक का बेरोज़गारी भत्ता वितरित

☞ योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगे

ऑनलाईन आवेदन तथा योजना की पूरी जानकारी के लिए http://admis.hp.nic.in/unemp पर log in करें

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम रोज़गार कार्यालय या निदेशालय, श्रम एवं रोज़गार में lep-hp@nic.in पर सम्पर्क करें

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा बेरोज़गार युवाओं के हित में जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

निदेशक लोकसंपर्क को हटाने के चुनाव आयोग ने दिये निर्देश

सेवा विस्तार एवम् पुनः नियुक्ति पाये अन्य अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज

शिमला/शैल। प्रदेश विधानसभा के चुनावों के परिदृश्य में प्रदेश की परिस्थितियों का आंकलन करने शिमला पहुंची केन्द्रिय चुनाव आयोग की पूरी टीम के समक्ष राजनीतिक दलों द्वारा रखी गयी प्रशासनिक वस्तुस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सरकार को लोक संपर्क विभाग के निदेशक आर.एस.नेगी को तुरन्त प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये हैं। स्मरणीय है कि नेगी को सरकार ने सेवानिवृति के बाद एक साल का सेवा विस्तार दिया था। नेगी की ही तरह कई अन्य अधिकारियों को भी सेवानिवृति के बाद या तो सेवा विस्तार या फिर पुन: नियुक्तियां दी गयी है। ऐसे अधिकारियों को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव काम से नही जुड़े होने चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि ऐसे अधिकारियों की कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरन्त कारवाई की जायेगी। स्मरणीय है कि भाजपा ने जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबित पात्रा की पत्रकार वार्ता में ''हिसाब मांगे – हिमाचल'' क्रम में वीरभद्र सरकार के खिलाफ पहला विधिवत हमला बोला था उस समय जारी किये गये प्रपत्र में कुछ अधिकारियों को अपने सीधे निशाने पर लिया था। इन अधिकारियों की सूची में डा. एच.एस. बवेजा मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया, लोक आयोग के नव – नियुक्त चेयरमैन सेवानिवृत मेजर जनरल धरम वीर सिंह राणा, आयोग की सदस्य श्रीमति मीरा वालिया, प्रदेश के मुख्य सचिव वी.सी. फारखा और मुख्यमन्त्री के सुरक्षा अधिकारी पदम ठाकुर के नाम शामिल रहे हैं। इस सूची में निदेशक लोक संपर्क का नाम नही था लेकिन अब चुनाव आयोग के सामने सेवानिवृत अधिकारियों की जिस तर्ज में स्थिति रखी गयी है उसमें अब निदेशक पर गाज गिरने से अन्य लोगों पर भी संशय की तलवार लटक गयी है।

भाजपा की शिकायत पर निदेशक लोक संपर्क का हटाया जाना यह इंगित करता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की आक्रमकता की धार कितनी तेज रहने वाली है। भाजपा पूरी आक्रमकता के साथ भ्रष्टाचार को केन्द्रित करके वीरभद्र और सरकार पर अपने हमले तेज करती जा रही है। शिमला में संबित पात्रा फिर केन्द्रिय मन्त्री रविशंकर प्रसाद और उसके बाद धर्मशाला में सुधांशु त्रिवेदी की अमित शाह की कांगड़ा रैली से पहले की गयी पत्रकार वार्ताओं में जिस तरह से भ्रष्टचार को मुद्दा बनाया गया था ठीक उसी तर्ज पर अमित शाह ने कागंड़ा में हुंकार रैली में भ्रष्टचार के आरोपों से वीरभद्र पर सीधा हमला बोला। शाह की रैली कांगड़ा में कितना सफल रही या असफल इस पर केन्द्रित होने से पहले ही 3 अक्बूतर को प्रधान मन्त्री नेरन्द्र मोदी द्वारा बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्ज़ का शिलान्यास किये जाने की चर्चा सामने आ गयी। प्रधानमन्त्री भी बिलासपुर में भ्रष्टाचार पर प्रत्यक्षत:/अप्रत्यक्षत: हमला बोलेंगे ही यह तो तय है। लेकिन भाजपा के इन हमलों का ठोस जवाब देने के लिये अभी तक कांग्रेस की ओर से कुछ भी सामने नही आ रहा है। बल्कि कांग्रेस के अन्दर तो अभी तक वीरभद्र बनाम सुक्खु द्वन्द ही खत्म नही हो पा रहा है। कांग्रेस के कौल सिंह और जी.एस.बाली जैसे वरिष्ठ मन्त्री ही अभी तक अपने – अपने स्टैण्ड के बारे में स्पष्ट नही हैं। विक्रमादित्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के एक परिवार से एक ही टिकट दिये जाने के स्टैण्ड पर चल रहे हैं जबकि उनके ही पिता मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह यह कह चुके हैं कि टिकटों के लिये पार्टी के अन्दर ऐसा कोई नियम नही है। विक्रमादित्य का जब पहली बार यह ब्यान आया था तब तो कौल सिंह ठाकुर ने भी यहां तक कह दिया था कि क्या ब्यान वीरभद्र सिंह को पूछकर दिया गया है। लेकिन अब दूसरी बार वही ब्यान आने से यह तो समझ आता है कि विक्रमादित्य का यह ब्यान अपने युवा संगठन की वकालत है क्योंकि यदि एक ही परिवार से दो – दो टिकट दिये जाने का चलन शुरू हो जाता है तो फिर युवाओं की बारी आ पाना संभव ही नही होगा। इसलिये युवा संगठन की वकालत के आईने से तो

ऐसा ब्यान जायज है। लेकिन आज लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस की जो हालत हो चुकी है उसे सामने रखते हुए इस समय ऐसे ब्यान केवल नुकसानदेह ही साबित होंगे।

क्योंकि राजनीतिक दलों ने सेवा विस्तार या पुन: नियुक्ति पाये अधिकारियों पर आयोग में आपति जताई है और कल को इसका सीधा निशाना मुख्यमन्त्री कार्यालय हो सकता है। राजनीतिक दलों ने मुख्यमन्त्री द्वारा इन दिनों की जा रही घोषणाओं पर एतराज उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह सब बजट प्रावधानों के बिना हो रहा है। राजनीतिक दलों ने सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाये गये अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स पर भी एतराज उठाया है और आयोग के निर्देशों पर उन्हें हटाने की नौबत आ जायेगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के मुद्दों को गंभीरता से लिया है और इसका प्रभाव सरकार पर पड़ना तय है।

इस समय पंजाब को छोड़कर देश के इस हिस्से में कांग्रेस कहीं नही है आज यदि हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है तो फिर कांग्रेस को पांव रखने के लिये भी कोई स्थान नही बचेगा। यह सही है कि हिमाचल में एक लम्बे अरसे से कभी कोई सरकार रिपीट नही हो पायी है। लेकिन इससे पहले नोटबंदी और फिर आयी जीएसटी तथा इन दोनो के कारण पैट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से जो मंहगाई और बढ़ गयी है उससे अचानक मोदी और उनकी सरकार बैकफुट पर आ गये हैं। इसी सबका परिणाम है कि आज राजस्थान को छोड़कर अन्य विश्वविद्यलायों में भाजपा के विद्यार्थी संगठन एबीवीपी को भारी हार का मुख देखना पड़ा है जो युवा विद्यार्थी एक समय मोदी के प्रति आकृष्ट हो गये थे आज उनका मोह भंग होना शुरू हो गया है। ऐसे में क्या प्रदेश कांग्रेस इन स्थितियों को सामने रखकर अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाती है या नही इस पर सबकी नजरें केन्द्रित हैं।

क्यों मेहरबान है सरकार .....पृष्ठ 1 का शेष

नही किया तो बवेजा ने इस पर 1.9. 2012 को राज्यपाल के पास बतौर चांसलर अपील दायर कर दी और राज्यपाल ने इस अपील पर 7.9. 2012 को जांच स्टे कर दी। इस स्टे के बाद अन्तत: 20.3.2013 को राज्यपाल ने डा. बवेजा को इस मामले मे क्लीनचीट दे दी। जबकि इसमें कोई जांच रिपोर्ट आयी ही नही। लेकिन इसी 2013 के दौरान ही बोर्ड में हुई कुछ खरीददारीयों और अन्य मामलों में डा. बवेजा के खिलाफ सरकार के पास शिकायतें आयी जिन पर कोई कारवाई नही हुई जबकि इस शिकायत में सबसे बड़ा आरोप 60 लाख के सीसीटीवी कैमरों की खरीद का रहा है। इनमें अरोप है कि टैण्डर आदि की सारी प्रक्रिया को पूरी तरह पूरी किये बिना ही यह कैमरे संजौली स्थित ग्लोबल नेटवर्क गुरूनानक बिल्ड़िग आईजीएमसी रोड़ से खरीद लिये गये। यह कंपनी मुख्यमन्त्री के एलआईसी ऐजैन्ट आनन्द चौहान की कही जाती है। और संभवत: इसी संपर्क का लाभ डा. बवेजा आज तक उठा रहे हैं। तभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे गंभीर मामले में अभी तक कोई कारवाई नही हो पा रही है।

21 विधायकों की सोसायटी को दी सरकार ने 30 बीघे ज़मीन

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार ने मन्त्रीमण्डल की पिछली बैठक में जुब्बड़हटी एयरपोर्ट के पास विधायकों की सोसायटी को 30 बीघे ज़मीन मकान बनाने के लिये दी है। सरकार का यह फैसला जैसे ही सार्वजनिक हुआ तभी से इस पर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गयी। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का तो यहां तक ब्यान आ गया कि न ज़मीन लेंगे और न ही लेने देंगे। इस फैसले पर यह नकारात्मक प्रतिक्रियाएं संभवत: इसलिये आयी हैं क्योंकि इससे पहले भी शिमला में दो स्थानों मैहली और हीरा नगर में सरकार ने विधायकों को ज़मीन दे रखी है।

स्मरणीय है कि विधायकों की पहली सोसायटी का पंजीकरण 9-9-86 को हिम लैजिस्लेचर भवन निर्माण सोसायटी के नाम से गठन हुआ था। उस समय इसके 123 सदस्य थे। इस सोसायटी को मैहली में 8 बीघे और हीरा नगर में 12 बीघे 16 बिस्वे ज़मीन मिली हुई है। इस सोसायटी के 31.3.15 तक हुए आडिट के मुताबिक इसके पास 8.50 लाख रूपया बचत खाते मे और 9.50 लाख रूपया एफडीआर के रूप में पूंजी है। इसका कार्यालय प्रदेश विधानसभा है। लेकिन यह सोसायटी किस तरह के काम कर रही है और इसके कार्यालय मे कितने कर्मचारी है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नही है, बल्कि इसका नियमित आडिट भी नहीं है। इसके अध्यक्ष विधान सभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी है और यह 13.8.14 को चुने गये थे।

इस सोसायटी के बाद 17.12. 2004 को न्यू लैजिस्लेचर भवन निर्माण सोसायटी के नाम से एक और पंजीकरण हुआ, इसके 21 सदस्य हैं। 2004 को पंजीकृत हुई इस सोसायटी की बैठक 5.3.2011 को हुई और इसमें सतपाल सत्ती इसके अध्यक्ष और सुधीर शर्मा इसके सचिव बने है। इसके पास पूंजी के नाम पर 2011 में 3.50 लाख रूपये बैंक में है। इसका कार्यालय भी विधानसभा ही दिखाया गया है, लेकिन इसके कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं और इसकी क्या गतिविधियां इसकी कोई जानकरी सार्वजनिक नही है। इसी के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि 2011 से लेकर आज तक इसका कोई आडिट भी नही हुआ है। सहकारिता नियमों के मुताबिक विधायको की इन दोनो सोसायटीयों में सहकारिता नियमों की कोई अनुपालना नही हो रही है। लेकिन सहकारिता विभाग इस संद्धर्भ में इनके खिलाफ कोई भी कारवाई नही कर पा रहा है।

इस नयी सोसायटी के इस समय भी 21 ही सदस्य है और अब सरकार ने इसी 21 सदस्यों की सोसायटी को 30 बीघे जमीन दी है लेकिन इससे पहले वाली सोसायटी के कितने सदस्यों ने उनकी मिली ज़मीन मकान बना रखे हैं। क्या इन मकानों को उपयोग आवास के लिये ही हो रहा है या इसका कोई वाणिज्यिक उपयोग भी हो रहा है। इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नही है। इसी के साथ यह भी एक सवाल चर्चा में चल रहा है कि 2004 में नयी सोसायटी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या दोनों सोसायटीयों के सदस्यता आदि नियमों में कोई अन्तर है और फिर 2004 में पंजीकृत हुई इस सोसायटी को अब 2017 में जमीन मांगने की क्यों आवश्यकता पड़ी, यदि सूत्रों की माने तो जब यह ज़मीन देने का प्रस्ताव तैयार हुआ और इसे विधि विभाग के परामर्श के लिये भेजा गया तो विधि विभाग ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन नही किया है। लेकिन विधि विभाग की राय को नजरअंदाज करके सरकार ने यह सौगात विधायकों को दे दी।

आज हमारे विधायकों को जहां सरकारी ज़मीन का तोहफा मिल गया वहीं पर यह लोग इस कार्यकाल में अपनी वेतन वृद्धि के मामलें में भी काफी सौभग्यशाली रहे हैं। क्योंकि 2015 तक इनका वेतन 20,000 रूपये मासिक था जो 6.2.15 को बढ़ाकर 30,000 रूपये हो गया। उसके बाद 10.5.16 को पुन: इनके वेतन में वृद्धि हुई और यह बढ़कर 55000 रूपये हो गया। इस समय हमारे विधायक सारे वेतन – भत्ते मिलाकर 2,10,000 रूपये प्रति माह प्राप्त कर रहे है। यही नही जिन निर्दलीय विधायकों ने जीतने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था और भाजपा ने इनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास दल – बदल कानून के तहत कारवाई किये जाने की याचिका दायर की थी उसका फैसला अध्यक्ष की कृपा से इस कार्यकाल में अब तक नही आया है। भाजपा ने भी इस पर उस समय जोर देना छोड़ दिया जब इन लोगों ने भाजपा का दामन थामने के संकेत दे दिये। इस तरह भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष की कृपा से इन निर्दलीयों का बड़ा नुकसान होने से बच गया। हमारे लोकतन्त्र की यही तो विशेषता है।